launch कर दी है, जिसमें England and Ireland सबसे आगे हैं। जैसा हमारे कई माननीय सदस्यों को चिन्ता रहती है कि इसके enforcement of the regulations को लेकर बहुत challenges आ रहे हैं और जो targets हैं, उन्हें हर हाल में achieve करना ही करना है। ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए कहना चाहता हूं कि we are the last generation, जो इस मद में कुछ कर सकती है। इसके बाद तो point of no return चालू हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार भी environmental emergency लागू करने पर विचार करेगी?

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, आज दुनिया में जिस तरह से प्रदूषण की मात्रा है, हमें समझना चाहिए कि भारत उसके लिए बहुत कम जिम्मेवार है और हमारा per capita emission भी कम है। यह इंडिया का 253 करोड़ टन है, चीन का 1 हजार करोड़ टन से ज्यादा है, युनाइटेड स्टेट्स का 500 करोड़ टन से ज्यादा है, even यूरोप का 343 करोड़ टन से ज्यादा है। मैं इंग्लैंड में बहुत बार गया हूँ, वहां पर carbon budgeting अच्छा काम करती है, लेकिन उनको बहुत कम करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा emission फैला रहे थे। हमारा per capital emission भी कम है और absolute terms में भी कम है, लेकिन हम अपने उदाहरण से दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि India, though not responsible for the problem, is a part of the solution for the problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 93. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, just one minute ... *(Interruptions)*... Just one minute, Sir. Please listen. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 93; Shri Sushil Kumar Gupta. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, through you, I would like to ask the Minister if he has read the correct figures. The number which he has given for per capita greenhouse gas emissions is not the correct one for India and other countries. Please check if it is in tonnes. ...*(Interruptions)*... We have taken this position with the UN. Please check the numbers.

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप सवाल तो पूछ नहीं सकते...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मैं फिर बता रहा हूँ कि इंडिया का per capita emission 1.92 टन है और जो पूरे देश का है, वह 253 करोड़ टन है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 93; Shri Sushil Kumar Gupta; not present. Shri Motilal Vora.

Quality of DD News

*93. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has launched a new digital service news gathering vans for Doordarshan News;

(b) if so, the details in this regard particularly with reference to improving the quality of DD News and enabling it to compete with other news channels and earn revenue for sustaining itself; and

(c) the measures taken to ensure live coverage of events by DO News, throughout the length and breadth of the country?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Prasar Bharati has hired 17 new Digital Satellite News Gathering (DSNG) HD (High Definition) Vans in Ooordarshan News with effect from 1st June, 2019, for transmitting HD television Signals *via* Satellite. Prasar Bharati also procured and deployed 9 HD DSNG vans last year, with state-of-the-art technology.

Visual quality of live coverage/live news reports has been improved with the deployment of DSNG vans and Outdoor Broadcast (OB)/Electronic Field Production (EFP) and reporting of news in HD mode.

(c) The live coverage on DD News across the country is carried out by deploying dedicated DSNG vans and 08 Vans etc in the vast Doordarshan Network. 31 Regional News Units across the country besides DD News in Delhi also contribute to the live coverage.

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि दूरदर्शन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आपने 1 जून 2019 को जो कदम उठाए थे, आज 1 जुलाई, 2019 है, इससे उसकी गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें केवल सरकारी समाचार ही आएंगे, जब कि बाकी चैनलों में लोग बेहिचक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा समाचार छपेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ? आपने इस मद में कितना खर्च किया?

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय वोरा जी।

श्री मोतीलाल वोरा: आपने इसमें कहा है कि एक महीने में 17 new Digital Satellite New Gathering HD Vans and nine High Definition DSNG vans का उपयोग किया। आखिर आपको इसकी गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको भी लगा कि दूरदर्शन को देखने वालों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय वोरा जी।

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय उपसभापति महोदय, जो हकीकत है, वह आपके सामने आनी चाहिए, बाकी चैनलों में लोग क्यों जाते हैं?

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय वोरा जी।

श्री मोतीलाल वोरा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसकी गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ?

श्री उपसभापति: माननीय वोरा जी, आपका सवाल आ गया है।

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, वोरा जी ने जो कहा है, वह एक सही मुद्दा है कि गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और उसमें लगातार प्रयास जारी है। अभी जो HD (High Definition) का 17 वाहन, पहले HD था, उसका एच.डी. प्रक्षेपण हो, इसके लिए हमने ये 17 वाहन launch किए हैं, देश के सभी भागों में दिए हैं और उससे गुणवत्ता बढ़ती है। सभी studios का modernization किया गया है, उसमें video walls लगे हैं। इसके कारण look and feel इम्प्रूव हुआ है। डी.डी. न्यूज़ के अनेक नए कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि आज भी terrestrial क्षेत्र में फ्री डिश, जिसके माध्यम से लोगों को 104 चैनल्स completely free मिलते हैं, उसके लिए किसी को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। इसके लिए केवल antenna लाकर लगाना पड़ता है और आज वह साढ़े तीन करोड़ से भी ज्यादा हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल है। DD News, being a national broadcaster, एक democratic frame में किसी भी national broadcaster का एक protocol होता है, how do you give coverage to the Treasury Benches, the Ruling Party and the Opposition? क्या ऐसा कोई protocol है कि आप opposition और ruling party के discourse को कैसे कवर करेंगे? There have been serious issues with this protocol.

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, प्रसार बैलेंस्ड हो, यह किसी भी सरकारी सेवा का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी निगरानी के लिए एक कमिटी भी बनी है जो यह देखती है कि हर महीने का बैलेंस्ड प्रक्षेपण हो रहा है या नहीं, सबकी न्यूज़ कवर होती है या नहीं। हम यह करते रहेंगे और यदि आपका भी कोई सुझाव हो, तो जरूर दें।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I would like to ask the hon. Minister this. Is it true that Doordarshan channels will soon be available in countries like Bangladesh and South Korea? Further, DD being a Government channel, in view of the climate change in the country as well as throughout the world, what steps are being taken by DD, as stated by the hon. Prime Minister, to spread message in respect of water conservation and plantation of trees through Doordarshan?

श्री प्रकाश जावडेकर: ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी नहीं चलाती है, वह 'प्रसार भारती' चलाती है। 'प्रसार भारती' के कानून में भी "genuinely autonomous" लिखा है। मैंने अभी वहाँ विज़िट किया था। जब उनके बोर्ड के साथ मेरी बातचीत हुई, तब मैंने कहा कि हम यह ensure करेंगे कि यह genuine autonomy के साथ ही काम करे। That is one.

सेकंड, आपने पर्यावरण के बारे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनका भी दर्शन होना चाहिए, इसलिए good stories, positive stories shoot की जाती

है। यदि आपके क्षेत्र में भी अच्छी स्टोरीज़ मिले, तो उनके बारे में भी आप सूचित कीजिए, हम वहाँ जाकर shooting करेंगे। हम वह भी दिखाएंगे, क्योंकि we believe that good message can be spread through public broadcasting more effectively.

देश में गंभीर जल संकट

***94. श्री प्रभात झा:** क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश के अनेक भागों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है और लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जल संकट को शीघ्र हल करने और देश के उन भागों में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) नीति आयोग की "स्ट्रैटजी फॉर न्यू इंडिया @75" के अनुसार, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर से घटकर 2011 में 1544 क्यूबिक मीटर हो गई है। चूंकि, जल, राज्य का विषय है अत: केंद्र सरकार जल संकट की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्यों के साथ कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के तहत ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए राज्यों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 17,25,808 ग्रामीण बसावटों में से, 13,98,292 ग्रामीण बसावटों (81.02%) में मौजूदा मानदंडों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, कुल 9182.58 लाख ग्रामीण आबादी में से, 7001.42 लाख ग्रामीण आबादी (76.25%) के पास 40 लीटर से अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अवसंरचना उपलब्ध है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत, राज्य, जल अभाव को कम करने के उपायों द्वारा अपने राज्यों के क्षेत्रों में पेयजल के संकट को कम करने के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. निधियों के 25% तक का उपयोग करने के लिए सशक्त हैं।

इसके अलावा, पेयजल की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- पेयजल स्रोतों को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) तथा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी.ए.डी. एण्ड डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम आदि के अंतर्गत भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।